



सीमा पार हथियार तस्करी और आतंकी साजिश पर एनआईए का बड़ा प्रहार, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी

देश की सुरक्षा के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साजिश को नाकाम करने की दिशा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने व्यापक कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई सीमा पार हथियार तस्करी, ड्रोन के जरिए भारत में भेजे गए विस्फोटकों और संदिग्ध आतंकी नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई। अधिकारियों का मानना है कि यह अभियान केवल हथियारों की तस्करी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाओं को अंजाम देना था।

जांच एजेंसियों के अनुसार इस पूरे नेटवर्क का संचालन पाकिस्तान में बैठे आतंकी तत्वों द्वारा किया जा रहा था। विशेष रूप से पाकिस्तानी आतंकी जसवीर चौधरी का नाम जांच के केंद्र में है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार जसवीर चौधरी भारत में सक्रिय अपने सहयोगियों और संपर्क सूत्रों के माध्यम से पंजाब, दिल्ली तथा अन्य राज्यों में आतंकी गतिविधियों की योजना बना रहा था। उसका उद्देश्य सीमा पार से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री पहुंचाकर देश के विभिन्न हिस्सों में दहशत फैलाना था।



शुक्रवार तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई में एनआईए की कई टीमों ने एक साथ अलग-अलग राज्यों में दहशत दी। उत्तर प्रदेश में पांच स्थानों, महाराष्ट्र में तीन तथा बिहार और राजस्थान में दो-दो स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों की गहन जांच की और वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल उपकरण तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जप्त किए। इन सामग्रियों की जांच से नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनकी गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस मामले की शुरुआत फरवरी महीने

आधुनिक हथियार, गोला-बारूद और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री शामिल थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि हथियारों की यह खेप किसी नेटवर्कगत अपराध या सीमित गतिविधि के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सुनिश्चित आतंकी साजिश थी। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि इन हथियारों और विस्फोटकों का इस्तेमाल

पंजाब, दिल्ली और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में एक साथ कई स्थानों पर आईईडी विस्फोट करने के लिए किया जाना था। यदि यह साजिश सफल हो जाती तो बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो सकता था और देशभर में भय एवं अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकता था। प्रारंभिक जांच में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने के बाद मामला एनआईए को सौंप दिया गया। 21 मार्च को राष्ट्रीय

जांच एजेंसी ने औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में ली और इसके बाद पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल शुरू की गई। एजेंसी ने विभिन्न राज्यों में सक्रिय संदिग्धों की गतिविधियों, उनके वित्तीय लेन-देन, संपर्क सूत्रों और डिजिटल संचार की निगरानी की। इसी क्रम में मिले साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन और उनके सहयोगी भारत में हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। पंजाब और जम्मू-कश्मीर से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बार ड्रोन के जरिए हथियार, गोला-बारूद, नकदी और मादक पदार्थ गिराए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। ड्रोन तकनीक भय एवं अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकती है। प्रारंभिक जांच में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने के बाद मामला एनआईए को सौंप दिया गया। 21 मार्च को राष्ट्रीय

जांच एजेंसी ने औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में ली और इसके बाद पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल शुरू की गई। एजेंसी ने विभिन्न राज्यों में सक्रिय संदिग्धों की गतिविधियों, उनके वित्तीय लेन-देन, संपर्क सूत्रों और डिजिटल संचार की निगरानी की। इसी क्रम में मिले साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन और उनके सहयोगी भारत में हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। पंजाब और जम्मू-कश्मीर से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बार ड्रोन के जरिए हथियार, गोला-बारूद, नकदी और मादक पदार्थ गिराए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। ड्रोन तकनीक भय एवं अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकती है। प्रारंभिक जांच में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने के बाद मामला एनआईए को सौंप दिया गया। 21 मार्च को राष्ट्रीय

जांच एजेंसी ने औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में ली और इसके बाद पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल शुरू की गई। एजेंसी ने विभिन्न राज्यों में सक्रिय संदिग्धों की गतिविधियों, उनके वित्तीय लेन-देन, संपर्क सूत्रों और डिजिटल संचार की निगरानी की। इसी क्रम में मिले साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन और उनके सहयोगी भारत में हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। पंजाब और जम्मू-कश्मीर से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में कई बार ड्रोन के जरिए हथियार, गोला-बारूद, नकदी और मादक पदार्थ गिराए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। ड्रोन तकनीक भय एवं अस्थिरता का माहौल पैदा हो सकती है। प्रारंभिक जांच में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आने के बाद मामला एनआईए को सौंप दिया गया। 21 मार्च को राष्ट्रीय

दार्जिलिंग शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच का रास्ता साफ, सरकार के रुख बदलने से तेज होगी कार्रवाई

कोलकाता। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर वर्षों से चल रहा विवाद अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के माध्यम से हुई कथित अनियमित नियुक्तियों की जांच को लेकर राज्य सरकार के बदले रुख ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई का रास्ता लगभग पूरी तरह साफ कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने के संकेत दिए जाने के बाद अब लंबे समय से रुकी हुई जांच प्रक्रिया के आगे बढ़ने की संभावना तेज हो गई है। इस घटनाक्रम को परिष्कृत बंगाल की राजनीति, प्रशासन और पहाड़ की सत्ता व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।



नवामने में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेन्द्र अधिकारी ने स्पष्ट संकेत दिए कि उनकी सरकार इस मामले में सीबीआई जांच के मार्ग में कोई बाधा नहीं बनने वाली है। उन्होंने कहा कि यदि भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच करनी है तो एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने

दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के संबंध में उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। दार्जिलिंग शिक्षक भर्ती विवाद पिछले कई वर्षों से राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ है। आरोप है कि जीटीए के तहत दार्जिलिंग और आसपास के पर्वतीय क्षेत्रों में 400 से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां अनियमित की गईं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और पात्रता, योग्यता तथा चयन संबंधी मानकों को दरकिनार कर कई लोगों को नौकरी दी गई।

इसी कारण यह मामला अदालत तक पहुंचा और बाद में इसकी जांच की मांग तेज होती गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अदालत का मानना था कि आरोपों को आवश्यक जांच आवश्यक है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप या सत्ता के दुरुपयोग की भूमिका रही या नहीं। हालांकि तत्कालीन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया लंबी खिंच गई और जांच की रफ्तार लगभग थम गई। अब सरकार के रुख में आए बदलाव को इस पूरे मामले में सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि राज्य सरकार वास्तव में अपनी

याचिका वापस लेती है तो सीबीआई को जांच आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की कानूनी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे उन सभी आरोपों और शिकायतों की गहन जांच संभव हो सकेगी, जिनके आधार पर भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप या सत्ता के दुरुपयोग की भूमिका रही या नहीं। हालांकि तत्कालीन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया लंबी खिंच गई और जांच की रफ्तार लगभग थम गई। अब सरकार के रुख में आए बदलाव को इस पूरे मामले में सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि राज्य सरकार वास्तव में अपनी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बिजली क्षेत्र के नियमन और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख चर्चित नाम भी समय-समय पर सामने आते रहे हैं। आरोपों के दायरे में पूर्व शिक्षा मंत्री अंब सरकार के रुख में आए बदलाव को इस पूरे मामले में सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि राज्य सरकार वास्तव में अपनी

अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में आयोग में नेतृत्व और सदस्यों की कमी को लेकर विभिन्न संगठनों और उपभोक्ता समूहों ने भी चिंता व्यक्त की थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुर्यकांत को अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे, ने मामले को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर विचार किया। सरकार ने अदालत को बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुषंगाने 27 मई को एक खोज एवं चयन समिति का गठन कर दिया गया है, जो डीईआरसी के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी करेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल समिति का गठन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समयबद्ध तरीके से नियुक्तियां सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। अदालत ने चयन समिति को निर्देश दिया कि वह पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाए तथा दो महीने के भीतर अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति सुनिश्चित

करने का प्रयास करे। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियामक संस्थाओं की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए रिक्त पदों को लंबे समय तक खाली नहीं रखा जाना चाहिए। पीठ ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि दो महीने बाद मामले की आगामी सुनवाई के समय एक अनुपालन शपथपत्र दायर किया जाए, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति और उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण हो। इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट केवल निर्देश देकर मामला छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी भी करेगा ताकि आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संस्था एनबी वाचडग की ओर से पेशा अधिवक्ता प्रणव सचदेवा ने अदालत से अनुरोध किया कि नियुक्तियों की प्रक्रिया को और अधिक तेज किया जाए तथा चयन समिति को एक महीने के भीतर रिक्त पद भरने का निर्देश दिया जाए। उनका तर्क था कि आयोग में लंबे समय से रिक्तियां बनी हुई हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव बिजली क्षेत्र के नियमन पर पड़

भारत-म्यांमार रिश्तों को मिलेगी नई गति, व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर होगी निर्णायक बातचीत

नई दिल्ली। भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के तहत म्यांमार के राष्ट्रपति चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंच रहे हैं। 30 मई से 2 जून तक चलने वाले इस दौर के दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया का सामरिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, यह यात्रा केवल एक औपचारिक राजनयिक कार्यक्रम नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक संतुलन से जुड़ा अहम अवसर मानी जा रही है।



देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। भारत और म्यांमार लगभग 1,600 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। यह सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे पूर्वीतट राज्यों से होकर गुजरती है। इन क्षेत्रों में लंबे समय से सक्रिय उग्रवादी संगठनों और सीमा पार गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए म्यांमार के साथ बेहतर समन्वय आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और म्यांमार ने संयुक्त सुरक्षा अभियानों के माध्यम से सीमा पार सक्रिय उग्रवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देश सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। सीमा प्रबंधन, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे विषय वार्ता के केंद्र में रह सकते हैं। भारत की 'एकट इस्ट नीति' के संदर्भ में भी

म्यांमार का महत्व बेहद बढ़ जाता है। दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंचने के लिए म्यांमार भारत का सबसे महत्वपूर्ण भूमि संपर्क मार्ग है। भारत लंबे समय से म्यांमार के माध्यम से आसियान देशों के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी उद्देश्य से कई संपर्क परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें सड़क, बंदरगाह और परिवहन नेटवर्क शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी योजनाएं दोनों देशों के आर्थिक सहयोग की आधारशिला हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से न केवल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पूर्वोत्तर भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में भी मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान इन परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। यात्रा का एक महत्वपूर्ण केंद्र व्यापार और निवेश भी होगा। मुंबई में म्यांमार के राष्ट्रपति उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, निवेश के नए अवसर तलाशने और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। सीमा प्रबंधन, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे विषय वार्ता के केंद्र में रह सकते हैं। भारत की 'एकट इस्ट नीति' के संदर्भ में भी

को और व्यापक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की बढ़ती सक्रियता और प्रभाव को देखते हुए भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। म्यांमार इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए म्यांमार के साथ दीर्घकालिक सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है। यात्रा से पहले म्यांमार के कुछ समूहों द्वारा संभावित विरोध प्रदर्शनों की चर्चाएं भी सामने आई हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया है और स्पष्ट किया है कि यह एक आधिकारिक राजकीय यात्रा है। भारत सरकार का ध्यान दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और सकारात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और म्यांमार केवल रणनीतिक साझेदार ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए मित्र देश हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। यही कारण है कि इस यात्रा को केवल राजनयिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच होने वाली वार्ता से कई महत्वपूर्ण समझौतों और नई पहलों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।



गरवी गुजरात हिन्दी



Jio Air Fiber



Jio Tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv



Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Roku Tv-US.UK



JioTV
CHENNAL NO. 2002

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

काँफी के कप में तैरता मिला काँकरोच

अहमदाबाद के चर्चित कैफे पर उठे गंभीर सवाल

अहमदाबाद के एक नामचीन कैफे में परोसी गई काँफी से काँकरोच निकलने की घटना ने शहर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। जिस स्थान पर लोग आरामदायक माहौल, बेहतर सेवा और गुणवत्तापूर्ण भोजन की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वही यदि उन्हें खाने-पीने की वस्तुओं में कीड़े-मकोड़े दिखाई दें तो यह केवल एक ग्राहक की शिकायत नहीं, बल्कि पूरे खाद्य सुरक्षा तंत्र पर गंभीर प्रश्नचिह्न बन जाता है। बॉडकदेव क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध 'मोचा कैफे' में सामने आई इस घटना ने न केवल ग्राहकों को हैरान किया है, बल्कि नगर प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली को भी कठपंरे में खड़ा कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, कैफे में पहुंचे एक ग्राहक ने काँफी का आँसू दिया था। जब काँफी उसके टेबल पर पहुंची और उसने कप को ध्यान से देखा तो उसमें एक काँकरोच तैरता हुआ दिखाई दिया।

यह दृश्य देखकर ग्राहक स्तब्ध रह गया। पहले तो उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कप को करीब से देखा तो काँफी में कीड़ा साफ नजर आया। इसके बाद ग्राहक ने तत्काल कैफे प्रबंधन से शिकायत की और वहां मौजूद कर्मचारियों से जवाब मांगा। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और कैफे में मौजूद अन्य ग्राहकों का भी ध्यान इस ओर गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्राहक ने केवल काँफी में काँकरोच मिलने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि कैफे की रसोई की स्वच्छता पर भी गंभीर सवाल उठाए। उसका दावा था कि भोजन और पेय पदार्थ तैयार किए जाने वाले क्षेत्र में साफ-सफाई का अभाव था तथा वहां काँकरोच और अन्य कीट दिखाई दे रहे थे। यदि यह आरोप सही है, तो यह स्थिति केवल एक कप काँफी तक सीमित नहीं बल्कि पूरे प्रतिष्ठान की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता



पैदा करती है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया। वीडियो सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब शहर के प्रतिष्ठित और महंगे कैफे में इस प्रकार की स्थिति है, तो सामान्य भोजनालयों और छोटे प्रतिष्ठानों

की हालत कैसी होगी। सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं ने अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) और खाद्य सुरक्षा विभाग से तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य पदार्थों में कीड़े या काँकरोच का मिलना केवल लापरवाही का मामला नहीं होता, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी

खतरा बन सकता है। काँकरोच अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं के वाहक माने जाते हैं। यदि वे खाद्य पदार्थों या भोजन तैयार करने वाले स्थानों के संपर्क में आते हैं, तो इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। फूड पॉइजनिंग, पेट संबंधी संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। अहमदाबाद में पिछले कुछ महीनों के दौरान भोजन में कीड़े-मकोड़े मिलने की घटनाओं ने पहले ही चिंता बढ़ा रखी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीते सात महीनों में शहर में भोजन और पेय पदार्थों में कीड़े मिलने से संबंधित लगभग 25 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। यह संख्या बताती है कि समस्या केवल किसी एक प्रतिष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक स्तर पर खाद्य स्वच्छता से जुड़ी चुनौती का संकेत है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद नगर निगम ने भी हाल के

समय में खाद्य प्रतिष्ठानों पर निगरानी बढ़ाई है। अधिकारियों का कहना है कि केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई पर्याप्त नहीं साबित हो रही थी, इसलिए अब नगर प्रशासन ने जीपीएमसी अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग कर अधिक कठोर कदम उठाने की तैयारी की है। इसके तहत स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई और अन्य प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं। चिंता की बात यह भी है कि स्वच्छता संबंधी शिकायतें अब केवल सड़क किनारे के ठेलों या छोटे भोजनालयों तक सीमित नहीं रह गई हैं। शहर के कई प्रतिष्ठित होटल, रेस्टोरेंट और प्रमुख कैफे भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। उपभोक्ता जब किसी प्रीमियम कैफे या रेस्तरां में अधिक कीमत चुकाते हैं, तो उनकी अपेक्षा केवल स्वादिष्ट भोजन तक सीमित नहीं होती। वे साफ-सुथरे

वातावरण, उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित खाद्य सामग्री को भी उम्मीद करते हैं। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं उपभोक्ताओं के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाती हैं। खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग के लिए नियमित कीट नियंत्रण, रसोई की सफाई, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और कर्मचारियों के प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य होनी चाहिए। यदि इन मानकों का पालन नहीं किया जाता, तो किसी भी समय ऐसी घटनाएं सामने आ सकती हैं जो न केवल ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करती हैं बल्कि प्रतिष्ठान की साख को भी नुकसान पहुंचाती हैं। मोचा कैफे में सामने आई यह घटना एक बार फिर इस सवाल को प्रमुखता से सामने लाती है कि क्या शहर के बड़े और प्रतिष्ठित खाद्य प्रतिष्ठान वास्तव में उन मानकों का पालन कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा केवल स्वादिष्ट भोजन तक सीमित नहीं होती। वे साफ-सुथरे

की आगामी कार्रवाई पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक कैफे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाद्य उद्योग के लिए चेतावनी साबित हो सकता है।

उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में केवल जुर्माना लगाना पर्याप्त नहीं है। नियमित निरीक्षण, पारदर्शी जांच व्यवस्था और दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ही ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगा सकती है। अहमदाबाद की यह घटना बताती है कि स्वाद और गंध के आकर्षण के पीछे छिपी वास्तविक स्वच्छता व्यवस्था की लगातार निगरानी कितनी आवश्यक है। आज जब लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर पहले से अधिक जागरूक हैं, तब खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए भी जिम्मेदारी और जवाबदेही का स्तर उतना ही ऊंचा होना चाहिए।

अहमदाबाद मंडल के सी एंड डब्ल्यू (C&W) कर्मचारियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई: टला एक्सप्रेस ट्रेन का कोच डिटेचमेंट

मात्र 28 मिनट में क्षतिग्रस्त वाल्व को बदलकर ट्रेन को गंतव्य के लिए किया रवाना, DRM श्री वेद प्रकाश ने रेल कर्मियों को 5,000 के सामूहिक पुरस्कार से नवाजा

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के कैरिज एवं वैगन (सी एंड डब्ल्यू) विभाग के कर्मचारियों ने आज अपनी तकनीकी दक्षता, दूरदर्शी योजना और उत्कृष्ट समन्वय का परिचय देते हुए एक बड़ा संकट टाल दिया। रेल कर्मियों की मुस्तेदी से ट्रेन संख्या 22950 देहरादून-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के एक कोच को अलग (डिटेच) होने से बचा लिया गया और ट्रेन का सुचारु व सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित किया गया।

क्या थी तकनीकी समस्या?
दिनांक 29 मई 2026 को उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यात्रा के दौरान ट्रेन संख्या 22950 दिल्ली सराय रोहिल्ला-

बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस के कोच संख्या M-2 में FIBA (Failure Indication and Brake Application) की स्थिति उत्पन्न हो गई। आठ रोल स्टेशन पर गहन जांच के दौरान तकनीकी टीम ने पाया कि ड्युलेक्स चेक वाल्व क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे लगातार एयर लीकेज हो रही थी। इस लीकेज के कारण अग्रणी टॉली के दोनों एयर सिलेंडर डिफ्लेट (पिचक) गए थे। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, ट्रेन को सी एंड डब्ल्यू स्टॉफ की निगरानी (एस्कॉर्टिंग) में 60 किमी प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से आगे चलाने की अनुमति दी गई।

अहमदाबाद मंडल की तैयारी

प्रातः 06:30 बजे अहमदाबाद कंट्रोल कार्यालय को यह सूचना मिली कि अहमदाबाद स्टेशन पहुंचने पर प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग करना पड़ सकता है। कोच डिटेच होने से यात्रियों को भारी असुविधा होती और ट्रेन भी अत्यधिक विलंबित होती। सूचना मिलते ही अहमदाबाद मंडल के सी एंड डब्ल्यू पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। टीम ने बिना समय गंवाए आवश्यक उपकरणों, फिटिंग्स और अतिरिक्त ड्युलेक्स चेक वाल्व की व्यवस्था की और ट्रेन के आने से पहले ही प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर पूरी मुस्तेदी के साथ तैनात हो गए।



मात्र 28 मिनट में 'मिशन सफल'

ट्रेन अपने निर्धारित समय से 62 मिनट की देरी से प्रातः 08:27 बजे अहमदाबाद स्टेशन पहुंची। ट्रेन के रुकते ही सी एंड डब्ल्यू की कुशल टीम ने युद्धस्तर पर काम शुरू किया। कर्मचारियों ने अपने तकनीकी कौशल का परिचय देते हुए मात्र 28 मिनट के रिकॉर्ड समय में क्षतिग्रस्त ड्युलेक्स चेक वाल्व को बदल दिया। इसके परिणामस्वरूप कोच को तुरंत फिर से सेवा योग्य (फिट) बना दिया गया। ट्रेन को बिना किसी अतिरिक्त समयहानि के और बिना कोच डिटेच किए सामान्य गति से आगे गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।

मंडल रेल प्रबंधक द्वारा सामूहिक पुरस्कार की घोषणा

अहमदाबाद मंडल के रेल कर्मियों की इस समर्पित कार्यशैली और त्वरित निर्णय क्षमता के कारण न केवल एक संभावित कोच डिटेचमेंट टला, बल्कि ट्रेन की समयबद्धता (Punctuality) पर पड़ने वाले असर को भी न्यूनतम रखा जा सका। मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने कर्मचारियों की इस सराहनीय कार्यकुशलता, सतर्कता और तत्परता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए संबंधित सी एंड डब्ल्यू टीम को 5,000 का सामूहिक पुरस्कार देने की घोषणा की है।

31 मई से 15 जुलाई तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को गांधीग्राम – प्रयागराज जंक्शन के बीच चलेगी द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल से एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। गांधीग्राम और प्रयागराज जंक्शन के बीच विशेष किराये पर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर मंडल श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, इस विशेष ट्रेन का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा—



ट्रेन संख्या 04112 गांधीग्राम – प्रयागराज जंक्शन द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 31 मई, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को गांधीग्राम से शाम 17:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात्रि 20:00 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 04111 प्रयागराज जंक्शन-गांधीग्राम द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 मई, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को प्रयागराज जंक्शन से शाम 16:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 15:30 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन निम्नलिखित स्टेशनों पर ठहरेगी— चांदखेड़ा रोड, मेहसाणा जंक्शन, पालनपुर जंक्शन, आबू रोड, सुमेरपुर जवाई बाँध, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर जंक्शन, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बाँदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर। इस विशेष ट्रेन में द्वितीय श्रेणी सामान्य (GS), शयनयान (Sleeper) एवं थर्ड एसी (3rd AC) श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे। ट्रेन संख्या 04112 के लिए टिकटों की बुकिंग 30 मई, 2026 (शनिवार) से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा IRCTC की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

शब्दों से नहीं, कार्रवाई से बनेगा भरोसा: अमेरिका को ईरान का स्पष्ट संदेश

तेहरान। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और शांति वार्ताओं को लेकर ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के प्रति अपना सख्त रुख स्पष्ट कर दिया है। ईरान के मुख्य वार्ताकार प्रयास करते हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस विषय पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है, जिससे स्थिति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ईरान का मानना है कि अतीत में कई बार समझौतों और आश्वासनों के बावजूद



यह संकेत दिया गया था कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस विषय पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है, जिससे स्थिति को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ईरान का मानना है कि अतीत में कई बार समझौतों और आश्वासनों के बावजूद

परिस्थितियाँ अपेक्षित दिशा में नहीं बढ़ीं। यही कारण है कि तेहरान अब किसी भी नई प्रक्रिया में शामिल होने से पहले व्यावहारिक परिणाम देखना चाहता है। गालिफक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने संदेश में कहा कि गारंटि और बयान पर्याप्त नहीं हैं। उनके अनुसार, विश्वास की नींव केवल उन कदमों पर रखी जा सकती है जो वास्तव में जमीन पर दिखाई

दें। पिछले महीने पाकिस्तान में आयोजित महत्वपूर्ण वार्ता में ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने ही किया था। इस वार्ता में क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क विरोध और भविष्य के कूटनीतिक विकल्पों पर चर्चा हुई थी। गालिफक ने यह भी कहा कि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति केवल बातचीत के बल पर नहीं बनाई है, बल्कि अपनी सैन्य क्षमता और प्रतिरोधक शक्ति के माध्यम से भी मजबूत की है। उन्होंने संकेत दिया कि देश की रक्षा क्षमता और मिसाइल कार्यक्रम ने ईरान को क्षेत्रीय समीकरणों में प्रभावशाली स्थान दिलाया है। इस बीच शांति प्रयासों में कतर की भूमिका भी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। कतर की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कतर के शासक से टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा की। कतर लंबे समय से पश्चिम एशिया के कई विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और वर्तमान परिस्थितियों में भी उसे एक महत्वपूर्ण संवाद

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भावनगर की छमाही बैठक संपन्न

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), भावनगर की छमाही बैठक का आयोजन दिनांक 29 मई, 2026 (शुक्रवार) को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर में अध्यक्ष – नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक किया गया। बैठक में भावनगर स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों एवं उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों, राजभाषा अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। बैठक के दौरान सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा राजभाषा संबंधी महत्वपूर्ण मद्दों पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इस अवसर पर राजभाषा हिंदी पत्रिका प्रकाशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को "सर्वश्रेष्ठ शील्ड", सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को "उत्कृष्ट शील्ड" तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को "प्रशंसनीय शील्ड"



प्रदान कर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने सभी विजेता संस्थाओं को बधाई देते हुए कहा कि अन्य कार्यालय भी इनसे प्रेरणा लेकर राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय योगदान देंगे। श्री दिनेश वर्मा ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने पर बल देते हुए सभी कार्यालयों से राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग का आग्रह किया। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक् शर्मा ने अपने संबोधन में कर्मचारियों को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के अंत में सचिव- नगर

राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री रामप्रीत मौर्य ने अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यालयों एवं प्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता हेतु आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ अनुवादक श्री परेश बी. मजीठिया द्वारा किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से मंडल लेखा परीक्षा कार्यालय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केंद्रीय विद्यालय, आयकर कार्यालय, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL), मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों एवं उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

गांधीग्राम और प्रयागराज के बीच द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन



यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा गांधीग्राम और प्रयागराज के बीच विशेष किराये पर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। इस विशेष ट्रेन का संचालन निम्नानुसार किया जाएगा—

ट्रेन संख्या 04112 गांधीग्राम – प्रयागराज द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 31 मई, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को गांधीग्राम से 17:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 20:00 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 04111 प्रयागराज-गांधीग्राम द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 30 मई, 2026 से 14 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को प्रयागराज से 16:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 15:30 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी। मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन चांदखेड़ा रोड, मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, सुमेरपुर जवाई बाँध, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बाँदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी एवं फतेहपुर स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में द्वितीय सामान्य श्रेणी, स्लीपर एवं एसी-3 टियर श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन संख्या 04112 की बुकिंग 30 मई, 2026 से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा IRCTC की वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

पश्चिम रेलवे द्वारा गांधीग्राम — प्रयागराज के बीच विशेष ट्रेन चलाई जाएगी

ट्रेन क्र.	प्रस्थान स्टेशन और गंतव्य	सेवा के दिन	प्रस्थान	आगमन
04112	गांधीग्राम - प्रयागराज (द्वि-साप्ताहिक)	31.05.2026 से 15.07.2026 तक	17:20 बजे (रवि और बुध)	20:00 बजे (दूसरे दिन)
04111	प्रयागराज - गांधीग्राम (द्वि-साप्ताहिक)	30.05.2026 से 14.07.2026 तक	16:15 बजे (शनि और मंगल)	15:30 बजे (दूसरे दिन)

होटल: चांदखेड़ा रोड, मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, सुमेरपुर, जवाई बाँध, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बाँदीकुई, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी और फतेहपुर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में।

संरचना: AC 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच।

समय, ठहराव और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं।

ट्रेन संख्या 04112 के लिए बुकिंग ता.30.05.2026 से सभी PRS काउंटर्स और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी।

उपरोक्त ट्रेन स्पेशल ट्रेन के रूप में स्पेशल किराए पर चलेगी।

पश्चिम रेलवे

www.indianrailways.gov.in

हमें लाइक और फॉलो करें

facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें।

सुरक्षित मातृत्व की ओर बढ़ता भारत, अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजातों की संख्या 90 प्रतिशत के पार

नई दिल्ली। भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएएस-6) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव की दर लगातार बढ़ रही है और अब 90.6 प्रतिशत नवजात अस्पतालों तथा स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म ले रहे हैं। यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सुरक्षित मातृत्व, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में भारत की बड़ी सफलता मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि संस्थागत प्रसव में हुई यह वृद्धि देश को सार्वभौमिक मातृ स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य के ओर करीब ले गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनएफएएस-6 रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2019-21 के दौरान संस्थागत प्रसव की दर 88.6 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 90.6 प्रतिशत हो गई है। इसका अर्थ है कि अब देश की अधिकांश गर्भवती महिलाएं प्रशिक्षित चिकित्सा

कर्मियों की निगरानी में अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सा संस्थानों में प्रसव करा रही हैं। इससे प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं से निपटने की क्षमता बढ़ी है और माताओं तथा नवजात शिशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि देश में प्रसवपूर्व देखभाल (एंटीनेटल केयर) सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 में मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में भारत की बड़ी सफलता मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि संस्थागत प्रसव में हुई यह वृद्धि देश को सार्वभौमिक मातृ स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य के ओर करीब ले गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनएफएएस-6 रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2019-21 के दौरान संस्थागत प्रसव की दर 88.6 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 90.6 प्रतिशत हो गई है। इसका अर्थ है कि अब देश की अधिकांश गर्भवती महिलाएं प्रशिक्षित चिकित्सा



महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। पहले जहां यह प्रतिशत 70 था, वहीं अब यह बढ़कर 76.2 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार कम से कम चार बार प्रसवपूर्व जांच कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत 58.5 से बढ़कर 65.2 हो गया है। यह बदलाव दर्शाता है कि महिलाएं अब गर्भावस्था को लेकर अधिक जागरूक हो रही हैं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के प्रति

प्रसवोत्तर देखभाल का प्रतिशत 79.1 से बढ़कर 85.3 हो गया है। यह बदलाव नवजात मृत्यु दर कम करने और शिशुओं को जीवन के शुरुआती दिनों में आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि संस्थागत प्रसव का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रसव के दौरान किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो जाती है। अस्पतालों में प्रशिक्षित डॉक्टरों, नर्सों और आधुनिक उपकरणों की मौजूदगी माताओं और शिशुओं दोनों के लिए जोखिम को काफी हद तक कम कर देती है। यही कारण है कि सरकार पिछले कई वर्षों से जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रही है। एनएफएएस-6 रिपोर्ट में मातृ पोषण के दो दिनों के भीतर डॉक्टर, नर्स, एएनएम या अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा नवजातों की जांच और

तक आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां लेने वाली महिलाओं की संख्या 44.1 प्रतिशत से बढ़कर 54.9 प्रतिशत हो गई है। वहीं 180 दिन या उससे अधिक समय तक इन सप्लीमेंट्स का सेवन करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 26 से बढ़कर 37.8 हो गया है। चिकित्सकों का मानना है कि आयरन और फोलिक एसिड की पर्याप्त मात्रा एनीमिया को रोकने, मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और नवजात के स्वस्थ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिपोर्ट में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े कई सकारात्मक संकेतक भी सामने आए हैं। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया के मामलों में कमी दर्ज की गई है। एनएफएएस-5 में जहां यह आंकड़ा 0.7 प्रतिशत था, वहीं एनएफएएस-6 में घटकर 0.5 प्रतिशत रह गया है। इसके पीछे स्वच्छता संबंधी जागरूकता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण कार्यक्रमों की सफलता को प्रमुख कारण माना जा रहा है। सबसे

उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रोटावायरस वैक्सीन कवरेज में हुई वृद्धि है। 12 से 23 महीने आयु वर्ग के बच्चों में रोटावायरस वैक्सीन की तीनों खुराक प्राप्त करने वालों का प्रतिशत 36.4 से बढ़कर 85.4 हो गया है। यह बढ़ती बच्चों को डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार देश में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 2014 में यह दर प्रति एक हजार जीवित जन्मों पर 45 थी, जो 2024 में घटकर 28 रह गई है। यानी एक दशक में बाल मृत्यु दर में लगभग 38 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सफलता का श्रेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, डायरिया नियंत्रण अभियान और मातृ-शिशु स्वास्थ्य योजनाओं को दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाओं की

पहुंच बढ़ने, आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम के सक्रिय योगदान तथा सरकारी योजनाओं की प्रभावी निगरानी ने इस परिवर्तन को संभव बनाया है। हालांकि अभी भी दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, कुपोषण और मातृ स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन ताजा आंकड़े यह संकेत देते हैं कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ बचपन की दिशा में भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अस्पतालों में बढ़ते प्रसव, बेहतर प्रसवपूर्व देखभाल, पोषण कार्यक्रमों का विस्तार और शिशु मृत्यु दर में कमी यह दर्शाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए निवेश और नीतिगत प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है। आने वाले वर्षों में यदि यही गति बनी रहती है तो भारत मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

गिर के शेरों पर मंडराया संकट, रहस्यमयी मौतों से वन विभाग सतर्क

अमरेली। एशियाई शेरों के दुनिया के एकमात्र प्राकृतिक आवास के रूप में प्रसिद्ध गुजरात का गिर वन क्षेत्र इन दिनों गंभीर चिंता के दौर से गुजर रहा है। मई 2026 में लगातार सामने आई शेरों की मौतों की घटनाओं ने वन विभाग, वैज्ञानिकों और वन्यजीव विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। अब तक आठ शेरों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, जिसके बाद पूरे गिर क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में इन मौतों के पीछे किसी संक्रामक बीमारी या वायरस के फैलने की आशंका जताई

जा रही है। यही वजह है कि वन विभाग ने तत्काल बचाव और निगरानी अभियान शुरू कर दिया है ताकि संक्रमण को अन्य शेरों और वन्यजीवों तक फैलने से रोका जा सके। शुरुआत में अधिकारियों को संदेह था कि शेर टिक के माध्यम से फैलने वाले बेबेसिया संक्रमण का शिकार हुए हैं। यह बीमारी जानवरों के रक्त को प्रभावित करती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बना देती है। हालांकि बाद में जांच के दौरान केनाइन डिस्टेंड वायरस (सीडीवी) की आशंका भी सामने आई,



जिसने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सीडीवी एक अत्यंत खतरनाक वायरल संक्रमण माना जाता है, जो मांसाहारी वन्यजीवों में तेजी से फैल सकता है और

बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बन सकता है। गुजरात के वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोदवाडिया ने मामलों की गंभीरता को स्वीकार करते हुए बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान गिर के राजस्व क्षेत्र में शेरों की मौतें दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी मृत शेरों के नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही मौतों

के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्र के आसपास लगभग दस किलोमीटर के दायरे में रहने वाले शेरों की विशेष निगरानी की जा रही है और कई जानवरों को अलग-थलग भी रखा गया है ताकि संभावित संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं और पिछले दो दिनों के दौरान किसी नई मौत की सूचना नहीं मिली है। इसके बावजूद विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहा है। जरूरत पड़ने पर देश के प्रमुख

वन्यजीव संरक्षण केंद्रों और विशेषज्ञ संस्थानों की सहायता लेने की भी तैयारी की जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वन्यजीव संरक्षण और उपचार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की मदद भी ली जा सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांभीरग ने उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, पशु चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसके बाद गांभीरग से एक विशेष जांच टीम को

गिर भेजा गया, जिसने गिर पूर्व और गिर पश्चिम के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक जांच शुरू कर दी है। वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं और पशु चिकित्सा केंद्रों का दौरा कर उपचार व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वन विभाग ने मृत शेरों के नमूने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौतों के पीछे बेबेसिया संक्रमण है, केनाइन डिस्टेंड वायरस है या कोई अन्य गांभीरग से एक विशेष जांच टीम को

भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। पूरे गिर क्षेत्र में विशेष सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत शेरों की गतिविधियों, उनके स्वास्थ्य और व्यवहार पर लगातार नजर रखी जा रही है। वन्यजीव चिकित्सकों की टीम बीमार या कमजोर दिखाई देने वाले जानवरों की तुरंत वन विभाग ने मृत शेरों के नमूने अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौतों के पीछे बेबेसिया संक्रमण है, केनाइन डिस्टेंड वायरस है या कोई अन्य गांभीरग से एक विशेष जांच टीम को

सप्ताह के दौरान सोना वायदा में 2681 रुपये, चांदी वायदा में 5346 रुपये और कूड ऑयल वायदा में 805 रुपये की भारी गिरावट

मुंबई: देश के अग्रणी कर्मांडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 22 से 28 मई के सप्ताह के दौरान कर्मांडिटी वायदा, ऑयल और इंडेक्स फ्यूचर्स में 7216572.63 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कर्मांडिटी वायदाओं में 263913.39 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कर्मांडिटी ऑयल में 6952658.79 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कर्मांडिटी ऑयल में कुल साप्ताहिक प्रीमियम टर्नओवर 35232.93 करोड़ रुपये का हुआ। आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 160743.17 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 159498 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंड्रा-डे में ऊपर में 159500 रुपये और नीचे में 153451 रुपये पर पहुंचकर, 159606 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2681 रुपये या 1.68 फीसदी की गिरावट के साथ 156925 रुपये प्रति

10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 1739 रुपये या 1.35 फीसदी गिरकर 127275 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल जून वायदा 231 रुपये या 1.43 फीसदी लुढ़ककर सप्ताह के अंत में 15928 रुपये प्रति 1 ग्राम बंद हुआ। सोना-मिनी जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 158390 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंड्रा-डे में ऊपर में 159259 रुपये और नीचे में 153149 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 2669 रुपये या 1.68 फीसदी आंधकर 156336 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। गोल्ड-टेन जून वायदा सप्ताह के आरंभ में प्रति 10 ग्राम 160451 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंड्रा-डे में ऊपर में 161298 रुपये और नीचे में 155525 रुपये पर पहुंचकर, 160872 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2309 रुपये या 1.44 फीसदी गिरकर 158563 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई



वायदा सप्ताह के आरंभ में 273800 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंड्रा-डे में 277399 रुपये के उच्च और 261000 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 274883 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 5346 रुपये या 1.94 फीसदी की गिरावट के साथ 269537 रुपये प्रति

किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 4785 रुपये या 1.72 फीसदी घटकर सप्ताह के अंत में 273803 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद

हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा सप्ताह के अंत में 4754 रुपये या 1.71 फीसदी गिरकर 273840 रुपये प्रति किलो हुआ। मेटल वर्ग में 29883.40 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जून वायदा सप्ताह के अंत में 2.25 रुपये या 0.17 फीसदी आंधकर 1360.4 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। जबकि जस्ता जून वायदा 2.55 रुपये या 0.7 फी स डी होकर यह कार्ट्रैक्ट सप्ताह के अंत में 367.55 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ। इसके सामने एल्यूमीनियम जून वायदा 3.85 रुपये या 1 फीसदी बढ़कर 387.5 रुपये प्रति किलो के

भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा जून वायदा सप्ताह के अंत में 1.8 रुपये या 0.88 फीसदी की वृद्ध के साथ 207.5 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इन जिनों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 73268.64 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स कूड ऑयल जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 9415 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंड्रा-डे में 9555 रुपये के उच्च और 8409 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 805 रुपये या 8.62 फीसदी लुढ़ककर 8537 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि कूड ऑयल-मिनी जून वायदा 800 रुपये या 8.57 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 8539 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इसके अलावा नैचुरल गैस जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 303 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंड्रा-डे में 315.8 रुपये के उच्च और 286.2 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 304.1 रुपये के पिछले बंद के

सामने सप्ताह के अंत में 9.8 रुपये या 3.22 फीसदी की मजबूती के साथ 313.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 9.8 रुपये या 3.22 फीसदी तेज होकर व्ह कॉन्ट्रैक्ट में 313.9 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर बंद हुआ। कृषि जिनों में मेंथा ऑयल जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 990.4 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 17.9 रुपये या 1.8 फीसदी गिरकर 975 रुपये प्रति किलो हुआ। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलोच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 91136.95 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 69606.21 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 22659.88 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 3525.70 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 135.87 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं

में 3519.68 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिनों के अलावा कूड ऑयल और कूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 46898.59 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 26196.76 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 16.49 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। ओपन इंटेरेस्ट सप्ताह के अंत में सोना के वायदाओं में 3064 टोंट, सोना-मिनी के वायदाओं में 26865 टोंट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 12721 टोंट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 184608 टोंट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 28190 टोंट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 10046 टोंट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 21926 टोंट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 56908 टोंट के स्तर पर था। कूड ऑयल के वायदाओं में 12658 टोंट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 20031 टोंट के स्तर पर था।

पश्चिम रेलवे द्वारा एफओबी गर्डर लॉन्चिंग हेतु, मरीन लाइन्स स्टेशन पर मेजर ब्लॉक लिया जाएगा

पश्चिम रेलवे द्वारा मरीन लाइन्स स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 एवं 4 के बीच फुट ओवर ब्रिज के गर्डरों की रोड क्रैन के माध्यम से लॉन्चिंग हेतु 30/31 मई, 2026 की मध्यरात्रि में मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापन के अनुसार, मरीन लाइन्स स्टेशन पर सभी लाइनों पर मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं रद्द अथवा आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।



से 00:30 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:35 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रह रहेगी।
 ▶ ट्रेन संख्या VR91024, जो विरार से 00:05 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:45 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रह रहेगी।
 ▶ ट्रेन संख्या VR90011 चर्चगेट के बजाय मुंबई सेंट्रल से 04:25 बजे शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। अतः यह सेवा चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच रह रहेगी।
 ▶ ट्रेन संख्या VR91018, जो विरार से 23:49 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:26 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रह रहेगी।
 ▶ ट्रेन संख्या BO91020, जो बोरोवली

से 00:30 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:35 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रह रहेगी।
 ▶ ट्रेन संख्या VR91024, जो विरार से 00:05 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:45 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रह रहेगी।
 ▶ ट्रेन संख्या VR90011 चर्चगेट के बजाय मुंबई सेंट्रल से 04:25 बजे शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। अतः यह सेवा चर्चगेट और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच रह रहेगी।
 ▶ ट्रेन संख्या VR91018, जो विरार से 23:49 बजे प्रस्थान कर चर्चगेट 01:26 बजे पहुंचती है, केवल मुंबई सेंट्रल स्टेशन तक ही चलेगी। अतः यह सेवा मुंबई सेंट्रल और चर्चगेट स्टेशनों के बीच रह रहेगी।
 ▶ ट्रेन संख्या BO91020, जो बोरोवली

और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों के बीच रह रहेगी।
 चर्चगेट तक / से पहली एवं अंतिम सेवाएं निम्नानुसार रहेंगी:
 ▶ विरार से चर्चगेट के लिए अंतिम ट्रेन, ट्रेन संख्या VR91012, विरार से 23:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा चर्चगेट 01:10 बजे पहुंचेगी।
 ▶ चर्चगेट से पहली निर्धारित स्लो ट्रेन, ट्रेन संख्या BO90025, चर्चगेट से 04:46 बजे प्रस्थान करेगी।
 ▶ चर्चगेट से पहली निर्धारित फास्ट ट्रेन, ट्रेन संख्या VR90021, चर्चगेट से 04:40 बजे प्रस्थान करेगी।
 ▶ यह भी सूचित किया जाता है कि रविवार, 31 मई, 2026 को दिन के समय कोई ब्लाक नहीं रहेगा।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के बीच चलाएगी दो स्पेशल ट्रेनें

यात्रियों की सुविधा तथा बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के बीच विशेष किराये पर दो विशेष ट्रेनें चलाएगी, जिससे अतिरिक्त यात्री यातायात को सुगमता से नियंत्रित किया जा सके। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापन के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:



1. ट्रेन संख्या 09021/09022 मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन संख्या 09021 मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद स्पेशल रविवार, 31 मई 2026 को मुंबई सेंट्रल से 06:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 12:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09022 अहमदाबाद - मुंबई सेंट्रल स्पेशल रविवार, 31 मई 2026 को अहमदाबाद से 15:10 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 21:45 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरोवली, वापी, सूरत, भरुक और वडोदरा स्टेशनों पर उदरेगी।

इस ट्रेन में विस्टाडोम, एग्जीक्यूटिव चेर कार, एग्जीक्यूटिव अनुभूति तथा एसी चेर कार कोच होंगे।
 2. ट्रेन संख्या 09043/09044 बांद्रा टर्मिनस - अहमदाबाद / वटवा - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन संख्या 09043 बांद्रा टर्मिनस - वटवा स्पेशल सोमवार, 01 जून 2026 को बांद्रा टर्मिनस से 23:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 08:00 बजे वटवा पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09044 अहमदाबाद - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल सोमवार, 01 जून 2026 को अहमदाबाद से 03:50 बजे प्रस्थान

करेगी और अगले दिन 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरोवली, पालघर, वापी और वडोदरा स्टेशनों पर उदरेगी। ट्रेन संख्या 09043 में उधना, आणंद और नडियाद स्टेशनों पर अतिरिक्त उदरार रहेगा। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09044 में भरुक और सूरत स्टेशनों पर अतिरिक्त उदरार रहेगा। इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे। इन ट्रेन संख्याओं 09021, 09022, 09043 एवं 09044 की बुकिंग 30.05.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के उदरार एवं संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

गर्मी बन रही जानलेवा, एक दिन में 3400 मौतों का दावा ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली। देश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी अब केवल असुविधा का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप लेती जा रही है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट ने चौंकाने वाला दावा किया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण देशभर में एक ही दिन में औसतन 3400 लोगों की मौत हो सकती है। वहीं यदि लू का प्रकोप लगातार पांच दिनों तक बना रहे तो इससे लगभग 30 हजार लोगों की जान जाने का खतरा पैदा हो जाता है। यह अध्ययन भारत में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव और उससे उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करता है। यह शोध इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के शोधकर्ता पीयूष नारंग और अशोक गाडगिल के साथ अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जलवायु विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। अध्ययन के लिए भारत के दस प्रमुख शहरों और विभिन्न राज्यों के तापमान, जनसंख्या घनत्व, मृत्यु दर तथा हीटवेव के प्रभावों से जुड़े आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। शोध के निष्कर्ष अंतरराष्ट्रीय जर्नल फ्रंटियर्स इन एनवायरनमेंटल हेल्थ में प्रकाशित हुए हैं, जिसने नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। रिपोर्ट में इन राज्यों का योगदान केवल 29 प्रतिशत के आसपास है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर और संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव अधिक विनाशकारी साबित हो रहा है।

डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते तापमान के कारण मानव शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है, जिससे हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हृदय संबंधी समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शोध में यह भी सामने आया है कि पांच दिन तक चलने वाली तीव्र लू का सबसे अधिक असर उत्तर प्रदेश पर पड़ सकता है। अनुमान के मुताबिक केवल उत्तर प्रदेश में ही पांच दिन की हीटवेव के दौरान लगभग 8100 लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा अहमदाबाद, जयपुर और सूरत जैसे शहरों में भी गर्मी के कारण प्रतिदिन लगभग 250 लोगों की जान जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट संरचनाओं की अधिकता, हरित क्षेत्रों की कमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण हीट आइलैंड प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, जिससे गर्मी का असर और अधिक घातक हो जाता है। रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि गर्मी से होने वाली कुल मौतों में लगभग 66 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों की है। जबकि देश की कुल जीडीपी में इन राज्यों का योगदान केवल 29 प्रतिशत के आसपास है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर और संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में गर्मी का प्रभाव अधिक विनाशकारी साबित हो रहा है।